प्रदेश के नए उत्पादों को दिलाएं जीआई टैग : नंदी

लखनऊ। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने उपादान योजनाओं के सरलीकरण के लिए नई निर्यात नीति जल्द लाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही विनिर्माण क्षेत्र व सेवा क्षेत्र पर निर्यात के लिहाज से ध्यान देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के उत्पादों की विविधता को देखते हुए नए उत्पादों को भी जीआई टैग दिलाया जाना उचित होगा।

मंत्री नंदी की विभागीय कामकाज की समीक्षा बैठक में निर्यात आयुक्त व अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म लघु एवं

योजनाओं और प्रक्रिया का होगा सरलीकरण, निर्यातकों को देय उपादान राशि में वृद्धि होगी

मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में निर्यात नीति जारी हो चुकी है। उपादान योजनाओं को अधिक युक्तिसंगत बनाया जाना है। इससे आवेदन की प्रक्रिया का सरलीकरण होगा। निर्यातकों को देय उपादान राशि में वृद्धि होगी। आवेदन प्रक्रिया को फिर ऑनलाइन बनाया जाएगा। जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति का गठन किया जा चुका है। जिला निर्यात कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सहगल ने अवगत कराया कि भू-आबद्ध निर्यातक राज्यों में प्रदेश को 2021 में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।

वहीं, औद्योगिक विकास मंत्री ने निर्यात नीति शीघ्र लागू करने के लिए जरूरी कार्यवाही जून तक पूरी करने के निर्देश दिए। कहा कि सारथी एप में निर्यात से जुड़े विषयों की व्यापक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अध्ययन किया जाए। ओवरसीज ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर्स की स्थापना का कार्य सुनिश्चित हो। प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति की बैठकों का आयोजन किया जाए। उनकी समस्याओं को उच्च स्तर पर भेजा जाए। निर्यात आयुक्त ने कहा कि विगत पांच वर्षों में प्रदेश के निर्यात में लगभग 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2021-22 में एक लाख पचास हजार करोड़ का निर्यात संभावित है।

मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय मेलों व प्रदर्शनियों को चिह्नित करते हुए अधिकाधिक निर्यातक इकाइयों को प्रतिभाग कराए जाने के निर्देश भी दिए। कहा कि प्रदेश के उत्पादों की विविधता को देखते हुए कई नए उत्पादों को भी जीआई टैग दिलाया जाना उचित होगा। ब्यूरो

सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान